



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 199]

नई दिल्ली, बुधस्वतिवार, मई 2, 2002/वैशाख 12, 1924

No. 199]

NEW DELHI, THURSDAY, MAY 2, 2002/VAISAKHA 12, 1924

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 मई, 2002

सं. 50/2002-सीमाशुल्क

सा.क्रा.नि. 316(अ).— अभिहित प्राधिकारी, चीन जनवादी गणराज्य और संयुक्त अरब अमीरात (सं0अ0अ0) में मूल रूप से उत्पादित या वहां से निर्यातित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के शीर्ष सं0 69.07 या 69.08 के अंतर्गत आने वाले विट्रीफाइड औद्योगिक टाइलों से भिन्न विट्रीफाइड और पोर्सिलेन टाइलों (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् “संबद्ध माल” कहा गया है) के आयात के मामले में भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 1, खंड 1, तारीख 3 दिसंबर, 2001 में प्रकाशित अपने प्रारंभिक निष्कर्षों के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि —

(क) चीन जनवादी गणराज्य और संयुक्त अरब अमीरात (सं0अ0अ0) (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् “संबद्ध देश” कहा गया है) में मूल रूप से उत्पादित या वहां से निर्यातित संबद्ध माल का, सामान्य मूल्य से कम मूल्य पर, भारत में निर्यात किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप पाटन हुआ है ;

(ख) भारतीय उद्योग को सारवान क्षति हुई है ;

(1)

(ग) संबद्ध देशों से आयातों द्वारा संरक्षित क्षति कारित हुई है ;

और, अभिहित प्राधिकारी ने यह आवश्यक समझा है कि संबद्ध देशों में मूल रूप से उत्पादित या वहां से निर्यातित संबद्ध माल के सभी आयातों पर अपना विनिश्चय लंबित रहने तक अनंतिम रूप से प्रतिपाटन शुल्क अधिरोपित किया जाए ;

और, अभिहित प्राधिकारी द्वारा संबद्ध मालों पर अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क अधिरोपित किए जाने की सिफारिश संबंधी पूर्वोक्त निष्कर्षों को चुनौती देते हुए अहमदाबाद स्थित गुजरात उच्च न्यायालय में 2001 का एक विशेष सिविल आवेदन सं० 11935 फाइल किया गया था ;

और, अहमदाबाद स्थित गुजरात उच्च न्यायालय ने 2002 के सिविल आवेदन सं० 96 और 2002 के सिविल आवेदन सं० 148 के साथ 2001 के विशेष सिविल आवेदन सं० 11935 में अपने तारीख 9 जनवरी, 2002 के आदेश द्वारा केन्द्रीय सरकार को निदेश दिया कि वह अनंतिम शुल्क की अधिसूचना जारी किए जाने से पूर्व विधि के अनुसार याचियों के अभ्यावेदनों पर विचार करे और मध्यपेक्षियों को भी अन्य पक्षकारों के साथ अभ्यावेदन करने का अवसर प्रदान करे ;

और, केन्द्रीय सरकार, याची और मध्यपेक्षियों द्वारा उठाए गए मुद्दों पर गहनता से विचार करने और उस पर अभिहित प्राधिकारी की टिप्पणी पर विचार करने के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि अभिहित प्राधिकारी के पूर्वोक्त निष्कर्षों में हस्तक्षेप करने का कोई मामला नहीं बनता है ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, प्रतिपाटन शुल्क का निर्धारण और संग्रहण तथा क्षति का अवधारण) नियम, 1995 के नियम 13 और नियम 20 के साथ पठित उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अभिहित प्राधिकारी के उपर्युक्त निष्कर्षों के आधार पर, चीन जनवादी गणराज्य और संयुक्त अरब अमीरात (सं०अ०अ०) में मूल रूप से उत्पादित या वहां से निर्यातित उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची के शीर्ष सं० 69.07 या 69.08 के अंतर्गत आने वाली वर्टिफाइड औद्योगिक टाइलों से भिन्न उक्त वर्टिफाइड या पॉर्सिलेन टाइलों पर, जब किसी निर्यातकर्ता या उत्पादक द्वारा निर्यात किया जाए और भारत में उसका आयात किया जाए, उस दर पर प्रतिपाटन शुल्क अधिरोपित करती है, जिसकी संगणना प्रति वर्गमीटर 13.62 प्रति वर्गमीटर अमेरिकी डालर और ऐसे आयातित संबद्ध माल के प्रति वर्गमीटर अवतरित मूल्य के बीच के अंतर के रूप में की जाएगी ।

2. इस अधिसूचना के अधीन अधिरोपित प्रतिपाटन शुल्क .../.../... 2002 तक, जिसमें वह दिन भी सम्मिलित है, प्रभावी होगा और भारतीय करेंसी में संदेय होगा।

स्पष्टीकरण—इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए,—

(क) “अवतरण मूल्य” से सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) के अधीन यथावधारित निर्धारणीय मूल्य अभिप्रेत है और इसमें उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 3, 3क, 8ख, 9 और 9क के अधीन उद्ग्रहीत शुल्कों को छोड़कर सभी सीमाशुल्क सम्मिलित हैं ;

(ख) ऐसे प्रतिपाटन शुल्क की संगणना के प्रयोजनों के लिए लागू विनिमय दर वह होगी जो उक्त सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (3) के खंड (क) के उपखंड (i) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए, समय-समय पर जारी की गई भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की गई है और विनिमय दर के अवधारण के लिए सुसंगत तारीख वह तारीख होगी जिस तारीख को उक्त सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 46 के अधीन प्रवेश पत्र प्रस्तुत किया जाता है।

[फा.सं. 354/214/2001-सीआरयू]

जी.डी. लोहानी, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd May, 2002

No. 50/2002-CUSTOMS

G.S.R. 316(E).—WHEREAS in the matter of import of vitrified and porcelain tiles, other than vitrified industrial tiles (hereinafter referred to as “the subject goods”), falling under heading 69.07 or 69.08 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), originating in, or exported from, the People’s Republic of China and United Arab Emirates (UAE), the Designated Authority *vide* its preliminary findings, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 3rd December, 2001, has come to the conclusion that—

- (a) the subject goods, originating in, or exported from, the People’s Republic of China and United Arab Emirates (UAE) (hereinafter referred to as “the subject countries”) have been exported to India below normal value, resulting in dumping;
- (b) the Indian industry has suffered material injury;
- (c) the injury has been caused cumulatively by the imports from the subject countries;

AND WHEREAS the Designated Authority has considered it necessary to impose anti-dumping duty, provisionally, pending final determination, on all imports of the subject goods, originating in, or exported from, the subject countries;

AND WHEREAS Special Civil Application No. 11935 of 2001 was filed in the High Court of Gujarat at Ahmedabad challenging the aforesaid findings of the Designated Authority recommending imposition of provisional anti-dumping duty on the subject goods;

AND WHEREAS the High Court of Gujarat at Ahmedabad, vide order dated the 9th January, 2002, in Special Civil Application No. 11935 of 2001 with Civil Application No. 96 of 2002 and Civil Application No. 148 of 2002, directed the Central Government to consider the representation of the petitioner in accordance with law before issuing the notification of provisional duty and the interveners shall also be given an opportunity to make a representation along with other parties;

AND WHEREAS the Central Government, after having considered at length the issues raised in the representations of the petitioner and interveners and the comments of the Designated Authority thereon, have come to the conclusion that there is no case for interfering with the aforesaid findings of the Designated Authority;

NOW, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 9A of the said Customs Tariff Act, read with rules 13 and 20 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, the Central Government, on the basis of the above findings of the Designated Authority, hereby imposes on vitrified or porcelain tiles, other than vitrified industrial tiles, falling under heading 69.07 or 69.08 of the First Schedule to the said Customs Tariff Act, originating in, or exported from, the People's Republic of China or United Arab Emirates (UAE), when exported by any exporter or producer, and imported into India, an anti-dumping duty at the rate which shall be calculated as the difference between US \$ 13.62 per square metre and the landed value of such imported subject goods in US \$ per square metre.

2. The anti-dumping duty imposed under this notification shall be effective upto and inclusive of the 1st day of November, 2002, and shall be payable in Indian currency.

Explanation - For the purposes of this notification,-

(a) "landed value" means the assessable value as determined under the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and includes all duties of customs except duties levied under sections 3, 3A, 8B, 9 and 9A of the said Customs Tariff Act;

(b) rate of exchange applicable for the purposes of calculation of anti-dumping duty shall be the rate which is specified in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), issued from time to time, in exercise of the powers under sub-clause (i) of clause (a) of sub-section (3) of section 14 of the said Customs Act, and the relevant date for the determination of the rate of exchange shall be the date of presentation of the bill of entry under section 46 of the said Customs Act.

[F.No. 354/214/2001-TRU]
G.D. LOHANI, Under Secy.